Issue-12; Vol.01, Sept. 2021 Impact Factor: 6.003 (I2OR)
ISSN–2231-1130
VEETHIKA

# व्यावसायिक शिक्षा के परिप्रेक्ष्य में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 : एक विश्लेषणात्मक अध्ययन

**राशी रस्तोगी**
शोधार्थी
ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती भाषा विश्वविद्यालय, लखनऊ

**डॉ नलिनी मिश्रा**
सहायक आचार्य
ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती भाषा विश्वविद्यालय, लखनऊ

***शोध–सार***

*किसी भी देश के विकास में उस देश की शैक्षिक व्यवस्था का बहुत अधिक महत्व होता है, अगर उस शिक्षा का मुख्य उद्देश्य विद्यार्थियों का सर्वांगीण विकास कर व्यवसाय दिलाना एवं विद्यार्थियों को जीविकोपार्जन योग्य बनाना हो तो उस देश का विकास निश्चित होता है । शिक्षा अपने वास्तविक उद्देश्य और लक्ष्य की प्राप्ति तभी कर सकती है जब वह शिक्षा व्यावसायिक शिक्षा हो । वर्तमान में शिक्षा की गुणवत्ता को ध्यान में रखते हुए जरूरी है कि शिक्षा को पूर्णता व्यावसायिक शिक्षा में परिवर्तित किया जाए। मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक के द्वारा भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में 34 वर्षों की दीर्घअवधि के बाद 29 जुलाई 2020 को 21वीं सदी की पहली शिक्षा नीति व स्वतंत्र भारत की तीसरी शिक्षा नीति की घोषणा की गई । राष्ट्रीय शिक्षा नीति के निर्माण के लिए 8 जून 2017 में इसरो के पूर्व प्रमुख डॉ के. कस्तूरीरंगन की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया जिसने मई 2019 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति का मसौदा प्रस्तुत किया। शोधार्थी ने व्यावसायिक शिक्षा के परिप्रेक्ष्य में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 : एक विश्लेषणात्मक अध्ययन को अपने शोध पत्र का विषय बनाया है।*

***मुख्य शब्द*** *: व्यावसायिक शिक्षा, राष्ट्रीय शिक्षा नीति।*

## प्रस्तावना

व्यावसायिक शिक्षा विद्यार्थियों को व्यवसाय चुनने एवं व्यवसाय संबंधित योग्यता प्राप्त करने का अवसर प्रदान करती है। व्यावसायिक शिक्षा आधुनिक युग की नई मांग है। इसके महत्व को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा (NCF)2005 में इसे सम्मिलित किया गया है। शिक्षा के क्षेत्र में व्यावसायिक शिक्षा को जोड़ने का प्रथम प्रयास कोठारी आयोग ने सन् 1964 ई0 में किया। कोठारी आयोग ने सरकार को माध्यमिक शिक्षा के व्यावसायीकरण का सुझाव दिया। बाद में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में व्यावसायिक शिक्षा के संरचनात्मक व प्रबंधन ढांचे में सुधार पर ध्यान केंद्रित किया। इसके आधार पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 व संशोधित रूप 1992 तक + 2 कक्षा के 25% छात्रों को व्यावसायिक शिक्षा से जोड़ने का लक्ष्य निर्धारित किया। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 एक व्यापक नीति दस्तावेज है जो व्यावसायिक शिक्षा में सुधार पर व्यापक रूप से चर्चा करता है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत देश में व्यावसायिक शिक्षा का बहुत तेजी से विस्तार हुआ है । इसके अंतर्गत देश के समस्त शिक्षण संस्थानों को अपने पाठ्यक्रम में व्यावसायिक शिक्षा को शामिल करने के लिए कहा गया है।

## अध्ययन की आवश्यकता एवं महत्व

भारत में एक तरफ सितंबर 2020 के अनुसार बेरोजगारी दर 6.6% है ,वहीं दूसरी तरफ इंडिया स्किल रिपोर्ट 2020 के अनुसार देश में मात्र 46.21% युवा रोजगार परक क्षमताओं से युक्त है। मैनपावर टैलेंट सर्वे 2018 के अनुसार भारत में प्रतिभा कमी की दर 56% है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग द्वारा किए गए आकलन के अनुसार 15 से 29 वर्ष की आयु के बीच कुल आबादी में से केवल 2% ने औपचारिक व्यवसायिक प्रशिक्षण प्राप्त किया है। 12वीं पंचवर्षीय योजना 2012 – 17 के संकेत मिलता है कि 24 वर्ष की उम्र के 5% से भी कम भारतीय कर्मचारियों ने औपचारिक व्यवसायिक शिक्षा प्राप्त की है। इससे स्पष्ट है कि भारत में दक्षता की कमी है। यदि भारत के युवा वांछित दक्षता प्राप्त कर ले तो न केवल देश के अंदर बल्कि विदेशों

में भी रोजगार के पर्याप्त अवसर प्राप्त होंगे । इस दुष्चक्र से देश को निकालने के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में व्यावसायिक शिक्षा को प्रभावी बनाने पर जोर दिया गया है।

## राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में व्यवसायिक शिक्षा के प्रावधान

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का लक्ष्य "भारत को वैश्विक ज्ञान महाशक्ति बनाना" है। इसी को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में व्यावसायिक प्रशिक्षण के व्यावहारिक पहलुओं को पढ़ाने पर जोर दिया गया है । इसके अंतर्गत व्यावसायिक शिक्षा को और अधिक संरचनात्मक बनाने के लिए यह नीति एक विशेष क्षेत्र के लिए प्रासंगिक व्यवसायिक पाठ्यक्रमों के आवंटन के साथ एक उचित कौशल विश्लेषण पर बल देने की सिफारिश करता है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति क्रेडिट आधारित राष्ट्रीय कौशल योग्यता फ्रेमवर्क (NSQF) पर भी जोर देता है जिसे 2013 में पेश किया गया था।

- 2021 के दशक से व्यावसायिक शिक्षा को चरणबद्ध तरीके से सभी स्कूलों व उच्च शिक्षा संस्थानों में समन्वित करके सन् 2025 ई0 तक स्कूल व उच्च शिक्षा प्रणाली के माध्यम से कम से कम 50% विद्यार्थियों को व्यावसायिक शिक्षा तक पहुंच बनाने के लिए लक्ष्य एवं समय सीमा के साथ एक स्पष्ट कार्य योजना विकसित की जा रही है।
- राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में चरणबद्ध तरीके से सभी शिक्षण संस्थानों में व्यावसायिक शिक्षा कार्यक्रमों को मुख्यधारा की शिक्षा में एकीकृत करने पर बल दिया गया है, जो श्रम की गरिमा और भारतीय कलाकारों से जुड़े विभिन्न व्यवसायों के महत्व पर जोर देगा।
- राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में कक्षा 6 से ही शैक्षिक पाठ्यक्रम में व्यावसायिक शिक्षा को शामिल किया जाएगा एवं इंटर्नशिप की व्यवस्था की जाएगी।
- राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में कक्षा 6 से 8 तक के विद्यार्थियों में व्यावसायिक शिक्षा प्राप्त करने पर अधिक ध्यान दिया जाएगा। इसमें प्रत्येक विद्यार्थी को बागवानी ,मिट्टी के बर्तन, लकड़ी का काम एवं बिजली के काम आदि में से में से कम से कम एक व्यावसायिक पाठ्यक्रम का अध्ययन अनिवार्य होगा।
- राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में वर्ष 2025 तक 50% विद्यार्थियों को शिक्षा उपलब्ध कराने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

## भारत में व्यावसायिक शिक्षा से संबंधित चुनौतियां

भारत में व्यावसायिक शिक्षा से संबंधित प्रमुख चुनौतियां हमारे समक्ष है जिसके कारण राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को व्यावहारिक रूप से अपनाने पर प्रमुख समस्याओं का सामना करना पड रहा है–

- **कुशल शिक्षकों का अभावः** वर्तमान में व्यावसायिक शिक्षा के क्षेत्र में कुशल शिक्षकों का अभाव है। ऐसे में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत व्यावसायिक शिक्षा हेतु की गई व्यवस्था के क्रियान्वयन में व्यवहारिक समस्याएं हैं।
- **वित्त पोषणः** वित्त पोषण का सुनिश्चित होना इस बात पर निर्भर करेगा कि शिक्षा पर सार्वजनिक व्यय के रूप में जीडीपी के प्रस्तावित 6 % खर्च करने की इच्छा शक्ति कितनी सशक्त है।
- **राज्यों का सहयोगः**शिक्षा एक समवर्ती विषय होने के कारण अधिकांश राज्यों के अपने स्कूल बोर्ड हैं इसलिए इस फैसले के वास्तविक कारण हेतु राज्य सरकारों को सामने आना होगा।
- **कम महत्व की शिक्षाः** व्यावसायिक शिक्षा को मुख्यधारा की शिक्षा से कम महत्व की शिक्षा माना जाता है और यह भी माना जाता है कि यह मुख्य रूप से उन विद्यार्थियों के लिए जो मुख्यधारा की शिक्षा के साथ सामंजस्य नहीं बिठा पाते हैं।
- **स्पष्ट मार्ग न होनाः**व्यावसायिक विषयों के साथ कक्षा 11वीं व 12वीं पास करने वाले विद्यार्थियों के पास अक्सर उच्चतर शिक्षा में अपने चुने हुए व्यवसाय क्षेत्र में आगे बढ़ने का स्पष्ट मार्ग नहीं होता है।
- **ड्रॉपआउटस :**व्यावसायिक शिक्षा प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या कम होने का प्रमुख कारण यह है कि अतीत में व्यवसायिक शिक्षा मुख्य रूप से कक्षा 11 का 12 और उससे ऊपर के कक्षा के ड्रॉपआउटस तक केंद्रीत थी।

## निष्कर्ष

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 21 वी सदी के भारत की जरूरतों को पूरा करने के लिए भारतीय शिक्षा प्रणाली में बदलाव हेतु जिस नई राष्ट्रीय शिक्षा

नीति 2020 को मंजूरी दी है, अगर उसका क्रियान्वयन सफल ढंग से होगा तो यह प्रणाली भारत को विश्व के अग्रणी देशों के समकक्ष ले आएगी। यह नीति बच्चे की क्षमता को पूरा करने में मदद करेगी एवं संज्ञानात्मक विकास के चरणों के साथ–साथ सामाजिक और शारीरिक जागरूकता पर भी उचित ध्यान देगी।

## संदर्भ सूची

1. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट – द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 डॉक्युमेंट।
2. वेबसाइट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, न्यू दिल्ली।
3. अग्रवाल, टी0. (2012). वोकेशनल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग इन इंडिया चैलेन्जेस, स्टेटस एंड लेबर मार्केट आउटकम्स, जनरल ऑफ वोकेशनल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग
4. मैक्लेन. आर0, एंड लाए, ए0. (2011). द फ्यूचर ऑफ टेक्निकल एंड वोकेशनल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग ग्लोबल चैलेन्जेस एंड पॉसिबिलिटीज, इंटरनेशनल जर्नल आफ ट्रेनिंग रिसर्च
5. https://www.oneindia.com/india/new-education-policy-2020-advantages-and-disadvantages-of-nep-3127811.html
6. https://www.nationalskillsnetwork.in/highlights-of-the-national-education-policy-2020/
7. https://www.udhyam.org/post/nep-2019-alignment-with-udhyam-shiksha
8. https://www.indiatoday.in/education-today/featurephilia/story/nep-2020-new-education-policy-is-a-positive-step-towards-nation-building-and-growth-here-s-how-
9. https://azimpremjiuniversity.edu.in/SitePages/pdf/MHRDNEPAzimPremjiFoundationResponse.pdf